



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2016/आश्विन 6, 1938

No. 356]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2016/ASVINA 6, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 22 सितंबर, 2016

सं. टीएएमपी/9/2016-बीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/9/2016-बीपीटी दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा अनुमोदित, संशोधित दरमानों में, एतद्वारा संलग्न आदेश के अनुसार संशोधन जारी करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/9/2016-बीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

...

आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस बालसुब्रमनियम, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितंबर 2016 के 17वें दिन पारित)

यह मामला, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (बीपीटी) के बारे में इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/9/2016-बीपीटी दिनांक 21 जून 2016, के अंतर्गत अनुमोदित, संशोधित दरमानों (एसओआर) में संशोधन से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के दरमानों (एसओआर) में सामान्य संशोधन के लिए वीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में दरमानों और कार्यनिष्पादन मानकों में संशोधन का अनुमोदन करते हुए, एक आदेश संख्या एएमपी/9/2016/-वीपीटी दिनांक 21 जून 2016 जारी किया गया था।

2.2. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान, निष्पादन मानकों सहित, 22 जुलाई 2016 को राजपत्र सं.305 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे।

3.1. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमानों के संदर्भ में वीपीटी ने दरमानों में कुछ संशोधन करने का अनुरोध किया है। दिनांक 21 जून 2016 के प्रशुल्क आदेश के संबंध में वीपीटी द्वारा उठाए गए बिंदुओं के प्रसंग में संबंधित उद्धरण और उन पर हमारे सिलसिलेवार विश्लेषण इस प्रकार हैं:

(i) **खंड 4 के अंतर्गत नोट-9, अनुसूची 4.1 -घाटभाड़ा**

(क) अनुसूची 4.1 के अंतर्गत नोट पर निर्धारित प्रावधान - 22 जुलाई 2016 को अधिसूचित संशोधित एसओआर में घाट भाड़ा प्रकार है:

*"शत-प्रतिशत ईओयू के लिए लाई गई सामग्री और यदि भारत सरकार के किसी दस्तावेज़ में उल्लेखित हो कि उपकरण/सामग्री का प्रयोग परियोजना के लिए किया जाएगा तो उसे परियोजना से संबंधित सामग्री माना जाएगा।"*

(ख) वीपीटी का अनुरोध :

वीपीटी ने कहा है कि परियोजनाओं के माल के लिए व्यावहारिक तौर पर घाट भाड़ा में 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है जो कि परियोजना कार्गो होने के कारण सीमा शुल्क प्राधिकारियों को स्वीकार्य है। अतः पत्तन ने अनुरोध किया है कि कथित नोट 9 से ये शब्द "शतप्रतिशत ईओयू के लिए लाई गई सामग्री और" हटा दिए जाएं

(ग) विश्लेषण:

(i) मामले पर कार्रवाई के दौरान विशाखापत्तनम स्टीम शिप एजेंट्स एसोसिएशन (वीएसएए) द्वारा सूचित किया गया था कि परियोजना कार्गो के लिए घाट भाड़ा में 25 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है। परंतु, परियोजना कार्गो क्या होता है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। जबकि वीएसएए द्वारा परियोजना कार्गो के स्पष्टीकरण के संबंध में दिनांक 21 जून 2016 के स्पीकिंग आदेश के साथ संलग्न टिप्पणियों के सारांश के पैरा 3 के क्रम सं. (5)(x) में, वीपीटी ने दिनांक 19 मई 2016 के अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि "शत-प्रतिशत ईओयू के लिए लाई गई सामग्री और यदि भारत सरकार के किसी दस्तावेज़ में उल्लेखित हो कि उपकरण/ सामग्री का प्रयोग परियोजना के लिए किया जाएगा तो उसे परियोजना से संबंधित सामग्री माना जाएगा।"। तदनुसार, वीपीटी के स्पष्टीकरण के आधार पर अनुसूची में नोट सं. 9 शामिल किया गया था।

(ii) वीपीटी द्वारा अब अनुरोध किया गया है कि कथित निर्धारित नोट से जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि व्यावहारिक तौर पर परियोजना के माल के लिए घाट भाड़ा प्रभार में 25 प्रति शत की छूट दी जाती है जो सीमा शुल्क प्राधिकारियों को स्वीकार्य है, से "शत-प्रतिशत ईओयू के लिए लाई गई सामग्री और" हटा दिए जाएं।

(घ) अनुशंसा :

वीपीटी के द्वारा किए गए उल्लेखों के परिप्रेक्ष्य में, खंड 4, अनुसूची सं. 4.1 के अंतर्गत वर्तमान नोट सं 9 से, वीपीटी के सुझाव अनुसार शब्दों को हटाते हुए आंशिक आशोधन किया जाता है।

(ii) **अनुसूची 4.7.4.1 में तालिका के नीचे नोट- खंड 4 के अंतर्गत कालानुपाती मजदूरी पर लेवी**

(क) निर्धारित प्रासंगिक अनुसूची 4.7.4.1. (नोट सहित) नीचे उद्धृत है:

**"4.7.4.1. समय-दर मजदूरी पर लेवी:**

विवरण	समय-दर मजदूरी पर लेवी: प्रतिशत में
कार्गो प्रस्तन प्रभाग से सभी प्रकार के कार्गो, तापीय कोयला सहित, की वैगन से उतरायी के लिए, कार्गो प्रहस्तन कामगारों की सेवाएं लेने के लिए।	150%

**नोट : शत-प्रतिशत मजदूरी में प्रभार्य होगी न कि लेवी ।**

1. उपर्युक्त लेवी दर, समय-दर मजदूरी व मजदूरों को देय पीस रेट, प्रचलित मजदूरी व्यवस्था/प्रोत्साहन योजना के संबंधित खंड के अनुसार है।
2. उपर्युक्त लेवी, स्टीवडोर्स द्वारा वीपीटी को देय होगी।
3. ऐसे मामलों में जहां सीएचडी कामगारों की मांग बर्थ में लगे हुए पोत पर कम है तो यह कर/वसूली वास्तविक घंटों के अनुसार की जाएगी।
4. पोतीय कार्य, पारी समाप्ति से पूर्व समाप्त होने की स्थिति में यह वसूली कार्य पूरा होने के वास्तविक घंटों के लिए प्रभार्य होगी।
5. क्रम सं. 3 व 4 के दोनो प्रकार के मामलों में शत प्रतिशत वसूली जाएगी।

(ख) वीपीटी का कथन:

वीपीटी का कथन है कि खंड 4.7.4.1. के अंतर्गत दिया गया है कि कालानुपाती मजदूरी दर (समय-दर मजदूरी) की लेवी संबंधी नोट कि यदि सीएचडी मजदूरों की मांग एक पारी से कम या पारी के समाप्त होने से (नोट 3 और 4) से पहले होती है तो 100 प्रतिशत मजदूरी वसूल की जाएगी। अतः वीपीटी ने तालिका के नीचे दिया गया अतिरिक्त नोट "शत प्रतिशत मजदूरी प्रभार्य होगी न कि लेवी" हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि यह पुनः लिखा गया है।

(ग) विश्लेषण:

- (i) अनुसूची 4.7.4.1. में तालिका के नीचे वीपीटी के दरमानों में शामिल नोट वीपीटी द्वारा प्रस्तावित एसओआर में नोट पर आधारित है।
- (ii) वीपीटी द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है कि वीपीटी द्वारा प्रस्तावित तथा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अनुसूची 4.7.4.1. के अंतर्गत नोट 5 में स्पष्ट किया गया है कि शतप्रतिशत मजदूरी वसूल की जाएगी। अतः दोहराव को दूर करने के उद्देश्य से, अनुसूची 4.7.4.1. के तुरत नीचे दिए गए नोट को हटाने का वीपीटी का सुझाव स्वीकार किया जाता है।

(घ) अनुशंसा :

वीपीटी द्वारा किए गए उपर्युक्त उल्लेखों के परिप्रेक्ष्य में अनुसूची 4.7.4.1.-समय-दर मजदूरी पर लेवी, में तालिका के तुरत नीचे दिए गए नोट को हटाया जाता है।

3.2. संक्षेप में, इस प्रकार पत्तन द्वारा दिए गए नवीन कारणों से दरमानों के वर्तमान प्रावधानों में दो आशोधनों का अनुमोदन किया जाता है।

4. क्योंकि ये आशोधन, प्राधिकरण के आदेश सं.टीएएमपी/9/2016-वीपीटी दिनांक 22 जुलाई, 2016 के आदेश द्वारा अधिसूचित दरमानों में आशोधन हैं, इसलिए ये आशोधन, संशोधित दरमानों के 22 जुलाई 2016 को राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात, अर्थात् 21 अगस्त, 2016 से प्रभावी होंगे।

5.1. परिणामतः और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र सोच विचार के पश्चात यह प्राधिकरण, प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/9/2016-वीपीटी दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा अनुमोदित वीपीटी के मौजूदा दरमानों में निम्नलिखित संशोधनों का अनुमोदन करता है :

(i) अनुसूची सं 4.1 में नोट सं 9 - दरमानों के खंड 4 के अंतर्गत घाट भाड़ा को निम्न से बदल दें:

**अनुसूची सं 4.1 में नोट सं (9) खंड 4 के अंतर्गत घाट भाड़ा**

*"यदि भारत सरकार के किसी दस्तावेज़ में उल्लेखित हो कि उपकरण/सामग्री का प्रयोग परियोजना के लिए किया जाएगा तो उसे परियोजना से संबंधित सामग्री माना जाएगा।"*

(ii) अनुसूची 4.7.4.1.-समय-दर मजदूरी पर लेवी, में तालिका के तुरंत नीचे दिए गए नोट - "शत प्रतिशत मजदूरी प्रभार्य होगी न कि लेवी", को हटाया जाता है।

5.2. मौजूदा दरमानों में अनुमोदित उपर्युक्त संशोधन प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/9/2016-वीपीटी दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा अधिसूचित, मौजूदा संशोधित दरमानों के प्रभावी होने की तिथि अर्थात् 21 अगस्त, 2016 से प्रभावी होंगे।

6. वीपीटी को, दरमानों में तदनुसार, आशोधन करने का परामर्श दिया जाता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

[विज्ञापन-III/4/आसा./143/16(245)]

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd September, 2016

**No.TAMP/9/2016-VPT.**—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby issues amendment to the revised Scale of Rates (SOR) approved by this Authority vide Order no.TAMP/9/2016-VPT dated 21 June 2016, as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports**

**Case No. TAMP/9/2016-VPT**

**Vishakhapatnam Port Trust**

...

**Applicant**

#### **QUORUM**

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

#### **ORDER**

(Passed on this 17th day of September, 2016)

This case relates to the amendment to the revised Scale of Rates (SOR) of the Visakhapatnam Port Trust (VPT) approved by this Authority vide Order No.TAMP/9/2016-VPT dated 21 June 2016.

2.1. This Authority has passed an Order No.TAMP/9/2016-VPT dated 21 June 2016, approving the revised Scale of Rates and Performance Standards with reference to the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR).

2.2. The revised Scale of Rates alongwith Performance Standards approved by this Authority were notified vide Gazette No.305 dated 22 July 2016.

3.1. With reference to the revised SOR approved by this Authority, the VPT has requested to consider a few amendments in its Scale of Rates. The points made by the VPT, the relevant extract from the tariff Order dated 21 June 2016 and our analysis thereon are dealt herein below in seriatim.

(i). **Note-9 under Section-4, Schedule 4.1 – Wharfage:**

(a). The provision prescribed at Note 9 under Schedule 4.1 – Wharfage in the revised SOR notified on 22 July 2016 is as follows:

*“The materials brought for 100% EOU and if any document issued by Government of India specifies that the equipment/material is utilized for project purpose, then it is treated as project consignment.”*

(b). Submissions made by VPT:

The VPT has submitted that in practice rebate of 25% in wharfage charges is given for project consignment that is accepted by customs Authorities as project cargo and hence the port has requested to delete **“the materials brought for 100% EOU and”** from the said Note No. 9.

(c). Analysis:

(i). During the processing of the case, the Visakhapatnam Steamship Agents Association (VSAA) had intimated that 25% concession in wharfage charges is proposed for project cargo. But, what is project cargo is not defined. As brought out in the summary of comments attached to the speaking Order dated 21 June 2016 at Sl. No. (5)(x) of Para 3, with reference to clarification sought by VSAA on what is project cargo, the VPT vide its letter dated 19 May 2016 has clarified that **“the materials brought for 100% EOU and if any document issued by Government of India specifies that the equipment/material is utilized for project purpose, then it is treated as project consignment”**. Accordingly, a note no. 9 was inserted in the Schedule based on the clarification of the VPT.

(ii). The VPT has now requested to delete the words **“the materials brought for 100% EOU and”** from the said note prescribed stating that in practice rebate of 25% in wharfage charges is given for project consignment that is accepted by customs Authorities as project cargo.

(d). Recommendation:

In view of the above submissions made by VPT, the existing Note no.9 under Schedule 4.1 under Section 4 is slightly modified by deleting the words as suggested by VPT.

(ii). **Note below the table in Schedule 4.7.4.1 - Levy on Time Rate Wages, under Section 4:**

(a). The relevant Schedule 4.7.4.1 along with the notes prescribed there in is given below:

**“4.7.4.1. Levy on Time Rate Wages:**

<i>Description</i>	<i>Percentage of Levy on Time Rate Wage</i>
<i>For all Cargo availing services of cargo handling worker from Cargo Handling Division including Thermal coal availing services of cargo handling worker for wagon unloading.</i>	<i>150%</i>

**Note: 100% wages will be charged but not levy**

**Notes:**

1. The levy indicated above is in addition to recovery of time rate wages and piece rates payable to workers as per the respective clauses of prevailing wage settlement/incentive scheme.

2. *The above levy is payable by the stevedores to the VPT.*
3. *In cases where requisition for CHD labour is less than a shift based on the berthing of the vessels, the levy will be charged at actual number of hours.*
4. *If a vessel is completed prior to closing of a shift, the levy will be limited, to actual number of hours till completion.*
5. *In both the cases at Sl.No.3 and Sl.No.4, 100% wages will be recovered.”*

(b). Submissions made by VPT:

The VPT has submitted that Note 5 to Levy of Time Rate Wages under Section 4.7.4.1 explains that 100% wages will be recovered in case requisition of CHD labour is less than a shift or prior to closing of a shift (note 3 and 4). Hence VPT has requested to delete the additional note “100% wages will be charged but not levy” prescribed just below the table as it is duplication.

(c). Analysis:

- (i). The note inserted in the SOR of VPT below the table in schedule 4.7.4.1 is based on the note proposed by VPT in the draft SOR.
- (ii). As rightly stated by VPT Note No. 5 under the schedule 4.7.4.1 proposed by VPT and approved by this Authority clarifies that 100% wages will be recovered. Hence, the suggestion of the VPT to delete the note immediately under the schedule 4.7.4.1 is accepted to remove the duplication.

(d). Recommendation:

In view of the above submissions made by VPT, the Note immediately below the table in Schedule 4.7.4.1- Levy on Time Rate Wages is deleted.

3.2. Thus, in short, for the reasons given by the port now, the two amendments to the existing provisions in the SOR are approved as suggestion by the VPT.

4. Since these are amendments to the SOR notified by this Authority vide Order No.TAMP/9/2016-VPT dated 22 July 2016, it is made effective from the date the revised SOR has come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR is Gazetted on 22 July 2016 i.e. with effect from 21 August 2016.

5.1. In the result, and for the reason given above, and based on collective application of mind, this Authority approves the following amendments in the existing Scale of Rates of VPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/9/2016-VPT dated 21 June 2016:

- (i). **The existing note no.9 in schedule 4.1 – Wharfage under Section 4 in the SOR is replaced with the following:**

**“Notes: (9) in schedule 4.1 wharfage under Section 4:**

*If any document issued by Government of India specifies that the equipment/material is utilized for project purpose, then it is treated as project consignment”.*

- (ii). The note immediately below the Schedule 4.7.4.1 – Levy on Time Rate Wages stating that “100% wages will be charged but not levy” is deleted.

5.2. The above amendments approved to the existing SOR shall come into effect from the date the revised SOR notified vide Order No.TAMP/9/2016-VPT dated 21 June 2016 has come into effect i.e. with effect from 21 August 2016.

6. The VPT is advised to modify the Scale of Rates accordingly.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/16(245)]